"कृषि लोगों के जीवन पर असर डालने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलाप है" - लोकसभा अध्यक्ष

चंडीगढ़, 29 अक्तूबर,2014: लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की संसदीय कृषि समिति की "संसदीय कृषि समितियों की भूमिका" विषय पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर विशिष्टजनों को संबोधित करते हुए श्रीमती महाजन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा हेतु औरजैव विविधता बनाए रखने तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय सरकारों को महत्वपूर्ण कृषि संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूक बनाना अत्यावश्यक है। कृषि खाद्य सुरक्षा, गरीबी को कम करने, पोषाहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के मामले में लोगों के जीवन पर प्रभाव डालने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलाप है।

यह टिप्पणी करते हुए कि भारत में कृषि प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहे हैं, लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि औद्योगीकरण और तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण तथा आवास और बुनियादी सुविधाओं की बढ़ती मांग के कारण लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं। इससे श्रमिकों और वस्तुओं की आवाजाही के संबंध में अवसंरचना में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है जिसका सामान्य रूप से समाज और विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र परगहरा असर पड़ता है।

श्रीमती महाजन ने कहा कि भारत की संसदीय कृषि संबंधी समिति का इस बारे में बहुत स्पष्ट मत है कि किसी भी नई आधुनिक प्रौद्योगिकी को तभी अपनाया जाना चाहिए जब यह सामाजिक और स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनुकूल हो, विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में व्यवहारिक हो तथा सरकार के कानूनों, विनियमों और नीतियों के अनुरूप हो। समिति अपने विचाराधीन किसी मुद्दे अथवा कानून पर जनमत प्राप्त करने की सिफारिश करके नीति-निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यह उल्लेख करते हुए कि भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए अनेक उपाय किए हैं, श्रीमती महाजन ने कहा कि वर्ष 2007 की "राष्ट्रीय कृषक नीति" में अन्य बातों के साथ-साथ उचित ब्याज दरों पर समय से, पर्याप्त और सुगम संस्थागत ऋण और किसानों के

लिए अनुकूल बीमा योजनाएं तथा एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसानों की कवरेज शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व व्यापार संगठन में भारत आजीविका, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों, जो गरीब किसानों और अन्य लोगों के हितों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, पर अपनी बात पर कायम रहा है। इसके अलावा कृषि में भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति का उद्देश्य सरकारी और निजी निवेश को आकर्षित करना है ताकि टैक्नोलॉजी, जानकारी और सेवाओं को किसानों तक पहुंचाया जा सके। सरकार "राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति" तैयार कर रही है ताकि यदि भूमि के उपयोग में परिवर्तन होते हैं तो वे भारत के सतत विकास के लिए हानिकारक न हों।

पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री, श्री प्रकाश सिंह बादल, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की प्रेज़ीडेंट, श्रीमती शिरीन शर्मिन चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुखबीर सिंह बादल, पंजाब विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री चरणजीत सिंह अटवाल, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के एशियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई और भारत क्षेत्रों के देशों की समितियों के सभापतियों तथा सदस्यों और विख्यात कृषि विशेषज्ञों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया।